



YouTube LIVE STREAM



वर्ष 13 • अंक: 138

CITY NEWS MUMBAI

दैनिक

सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

मुख्यमंत्री के नाम दम भरने वाले जीजाऊ कंपनी बे लागम अधिकारी भी डरते है कार्यवाही से...



भोला नगर का टेकेदार भी जीजाऊ के नक्शे कदम पर..

जीजाऊ, हबीब पटेल, विजय पटेल पर कोई लगाम नहीं

मिरा भयंदार (सिटी न्यूज मुंबई) मिरा भयंदार महानगर पालिका मे क्षेत्र मे सीमेंट रोड का कार्य जोरो शोर से चल रहा है जिस तरह से सब से ज्यादा घटिया निर्माण पालघर क्री कंपनी जीजाऊ कंट्रोलेशन को

संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते सब ज्यादा घटिया निर्माण जीजाऊ शहर मे कर रहा है. सूत्रों क्री माने तो जीजाऊ कंट्रोलेशन के संबध राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से होने के चलते उस पर कार्यवाही करने से

घबराते मनपा के अधिकारी भी घबराते है सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम दम भरने का काम जीजाऊ वाला करता है इस तरह क्री बात दबी जुबान मे मनपा के अधिकारी करते है . जीजाऊ

कंट्रोलेशन का सीसी रोड कुछ इस तरह से हो रहे है क्री एक और जहा सीसी रोड बनता है तो दूसरी और का खुदाई का काम चलते ही पहले जो सीसी रोड बन रहा होता है उसमे बड़ी बड़ी दरारे आ जाती है.या फिर रोड

का सरफेस पर गिट्टी बाहर निकल आ जाती है.रोड पर नियमित पानी भी दाला नहीं जाता रोड के निचे जो सीमेंट पाईप डाले गए है वह भी टूटे फूटे हुए है.सर्वाजनिक निर्माण के अभियंता और साइड इंजीनियर भी

काफी दबाव रहते है घटिया निर्माण होने के बाउजुद जीजाऊ पर कार्यवाही करने क्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है.सियासी नेता और विधायकों का समर्थन होने के चलते मनपा आयुक्त को कई शेष पृष्ठ 7 पर

आखिरकार आ गई फैसले की घड़ी

शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले में 10 जनवरी को निर्णय



राहुल नार्वेकर के फैसले पर टिका है शिंदे सरकार का भविष्य

फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय फैसले को अंतिम रूप दे रहा है. फैसला सुनाते वक्त सिर्फ मुख्य मुद्दों को ही शेष पृष्ठ 7 पर

मुंबई। आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों के

अयोग्यता मामले में फैसले की घड़ी आ गई। बुधवार 10 जनवरी को शाम

चार बजे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मनपा भी तैयार

शहर में स्वच्छता और होर्डिंग हटाने का आयुक्त का निर्देश



मुंबई। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मुंबई में आगमन हो रहा है। मोदी शिवडी नावा सेवा एम टी एच एल (MTHL) का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन पर मनपा प्रशासन तैयारी में जुट गई है। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल सोमवार को मनपा के जोन 1 और जोन 2 के शेष पृष्ठ 7 पर

8 जनवरी यौमे-ए-वफात पर विशेष मजलिस-ए-अहरार-उल-इस्लाम' पार्टी के संस्थापक सदस्या स्वतंत्रता सेनानी मुफक्की-ए-अहरार चौधरी अफज़ल हक

चौधरी अफज़ल हक, जिन्होंने एक ओर ब्रिटिश शासकों और दूसरी ओर रॉयल इंडिया मुस्लिम लीग' जैसी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वह मजलिस-ए-अहरार-उल-इस्लाम' के संस्थापकों में से एक थे, मुस्लिम लीग जिसके कारण पंजाब क्षेत्र में बड़ी सनसनी और देश में अशांति फैल गई। उनका जन्म 1895 में पंजाब के होशियारपुर के एक मुस्लिम राजपूत परिवार में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पुलिस विभाग में काम करना शुरू किया लेकिन जल्द ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खिलाफत और असहयोग आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। धीरे-धीरे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करीब आ गये। 1924 और 1926 में वे विधान परिषद के लिए चुने गये। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के



बहिष्कार का प्रस्ताव यह कहते हुए पेश किया कि ब्रिटिश सरकार की बात मानने से कोई फायदा नहीं होगा। मुस्लिम लीग के राजनीतिक रुख से नाखुश होकर, वह 1929 में 'मजलिस-ए-अहरार-उल-इस्लाम' के संस्थापकों में से एक बन गए। उन्होंने 'मजलिस-ए-अहरार-उल-इस्लाम' के अध्यक्ष के रूप में

काम किया। लोगों के बीच राष्ट्रवादी आदर्शों को बढ़ावा देना और उन्हें इस्लामी परंपरा में सही रास्ता दिखाना। हालाँकि मजलिस-ए-अहरार-उल-इस्लाम 1930 में एक राजनीतिक दल में तब्दील हो गया, लेकिन यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करीब था। 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया जिसके लिए उन्हें छह महीने की जेल हुई। उनके सम्मान में मुस्लिम लीग को वैचारिक रूप से चुनौती देने के प्रयासों और पंजाब क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने वाली अहरार पार्टी को उनके बौद्धिक समर्थन के लिए उन्हें रमुफक्की-ए-अहरार' के नाम से जाना गया। 1931 में चौधरी अफज़ल पहली बार पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1931 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में अहरार पार्टी का

नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने आध्यात्मिक और आर्थिक मुद्दों पर कई किताबें लिखीं। उन्होंने आजादी और स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझाते हुए 'आजादी-ए-हिन्द' लिखा और प्रकाशित किया। चौधरी अफज़ल हक, जिन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा सामने लाए गए भारत को विभाजित करने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की और एक गहन मुस्लिम विरोधी लीग अभियान चलाया, उनका 8 जनवरी, 1942 को लाहौर में निधन हो गया। (संदर्भ: द इम्पोर्टन्स-2, सैयद नसीर अहमद द्वारा, 9440241727) संकलन हसरत अलीशेरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेशफोन नंबर 8580533689

'विफलता का कारण मुशर्रफ का रुख, कश्मीर-आतंकवाद पर गलत इरादे'; किताब में आडवाणी पर भी बात



करीब दो दशक पहले साल 2001 में भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कवायद हुई थी। कारगिल के युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्तों की जमी बर्फ पिघलाने के लिए आगरा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तल्ख हो चुके संबंधों को सामान्य बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ की अगुवाई में दोनों देशों की शिखर वार्ता हुई। हालांकि, मुशर्रफ के अडियल रुख के कारण वार्ता बेनतीजा रही। इतिहास में आगरा शिखर वार्ता को लेकर कई दृष्टिकोण दर्ज हैं। ताजा घटनाक्रम में वाजपेयी के सहयोगी रहे राजदूत अजय बिसारिया ने कुछ अहम बिंदु सामने रखे हैं। उन्होंने वाजपेयी, मुशर्रफ के अलावा आडवाणी से जुड़ी बातें एक किताब की शकल में साझा की हैं। उन्होंने बताया है कि कश्मीर पर मुशर्रफ अपने उग्र विचारों से समझौता करने को राजी नहीं थे। आतंकवाद पर नकेल करने के मुद्दे पर मुशर्रफ के इरादे कमजोर थे। उन्होंने साफ किया कि 2001 में आगरा समिट के नाकाम होने का कारण लक्ष्मण आडवाणी का

कट्टरपंथी दृष्टिकोण नहीं, मुशर्रफ का रवेया है। वाजपेयी के कार्यकाल में प्रमुख सहयोगी रहे बिसारिया ने अपनी किताब में आगरा शिखर सम्मेलन के कई नाटकीय विवरणों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन, मुशर्रफ ने देश-दुनिया के प्रमुख समाचार पत्रों और टीवी नेटवर्क संपादकों से नाश्ते के दौरान बातचीत की। बकौल बिसारिया, मुशर्रफ ने कश्मीर पर अपनी कठोर स्थिति को 'उजागर' किया और आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर बताया। 'एंगर मैनेजमेंट: द ट्रबल डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान' शीर्षक वाली इस किताब में बिसारिया बताते हैं कि मुशर्रफ और मीडिया की बातचीत का सार्वजनिक प्रसारण हो रहा था। पर्यवेक्षकों को यह वार्ता के दौरान मध्य-शिखर रिपोर्ट जैसा लग रहा था। पाकिस्तान के कठोर विचार भारत पर थोपे जाने का एहसास हो रहा था। भारत की तरफ से तत्काल कोई ठोस और आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई। बिसारिया बताते हैं कि इस हाईप्रोफाइल आयोजन के कारण आगरा में अस्थायी प्रधानमंत्री कार्यालय

(PMO) जैसा बन चुका था। वे और वाजपेयी के प्रधान सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे ब्रजेश मिश्रा, टेलीविजन पर मुशर्रफ की टिप्पणियों को 'निराशा' के साथ देख रहे थे। बकौल पूर्व राजनयिक बिसारिया, ब्रजेश मिश्रा मेरी ओर मुड़े और कहा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी को इस घटनाक्रम के बारे में सूचित करने की जरूरत है। मिश्रा के मुताबिक वाजपेयी बैठक कक्ष के बाहर होने वाली हर चीज से बेखबर मुशर्रफ के साथ बातचीत कर रहे थे। राजदूत बिसारिया 22 साल पहले की घटना का जिक्र कर बताते हैं कि ब्रजेश मिश्रा ने कुछ पंक्तियां लिखीं। उन्होंने तुरंत टाइप कर दिया। इसमें लिखा गया था कि मुशर्रफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण हो रहा है। इसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अपने कट्टरपंथी रुख को दोहराने के साथ-साथ आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानियों के समान करार दिया। बिसारिया को उस कमरे में जाने की इ्यूटी मिली जहां वाजपेयी और मुशर्रफ के अलावा वार्ता से जुड़े बिंदुओं को लिखने वाले दो लोग बैठे थे। राजदूत बताते हैं कि कमरे में उनके प्रवेश से बातचीत बाधित हुई। दोनों नेताओं ने उनकी तरफ देखा। बकौल बिसारिया, 'मुशर्रफ बात कर रहे थे और वाजपेयी जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। मैंने बांस को पेपर सौंप दिया और कहा कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं।' उन्होंने बताया कि 'कमरे से बाहर निकलने के बाद, वाजपेयी ने पेपर देखा और इसे मुशर्रफ को पढ़कर सुनाया। वाजपेयी ने मुशर्रफ से कहा कि उनके व्यवहार के कारण

दोनों देशों की शिखर वार्ता में मदद नहीं मिल रही है। तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका पर बिसारिया बताते हैं कि चर्चित नैरेटिव है कि आडवाणी ने कश्मीर मुद्दे पर वीटो कर दिया, क्योंकि वह इस विषय पर पाकिस्तान के साथ नरमी दिखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, 'आडवाणी मीडिया रिपोर्टिंग के तिरछेपन (slant) से भली-भांति परिचित थे। इस कारण वे इस मामले में खलनायक बन गए।' जून 2022 में विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हुए बिसारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में बाद के दिनों में आई रिपोर्ट्स से साफ हुआ कि वास्तविकता अलग थी। लगभग वही मसौदा सामने आया, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत थे। बिसारिया बताते हैं कि दोनों देशों के मसौदा वक्तव्य में तत्कालीन पाकिस्तान विदेश मंत्री अब्दुल सत्तार के साथ जसवंत सिंह का भी जिक्र था। तत्कालीन रक्षा और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने वाजपेयी को इसकी जानकारी भी दी। वार्ता खत्म होने के बाद जैसे ही जसवंत कमरे से बाहर निकले, आडवाणी ने आह भरी और अंग्रेजी में कहा, कि अब वह 'फॉल मैन' होंगे। शिखर वार्ता की विफलता को लेकर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री रहे थे और वाजपेयी जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। मैंने बांस को पेपर सौंप दिया और कहा कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं।' उन्होंने बताया कि 'कमरे से बाहर निकलने के बाद, वाजपेयी ने पेपर देखा और इसे मुशर्रफ को पढ़कर सुनाया। वाजपेयी ने मुशर्रफ से कहा कि उनके व्यवहार के कारण

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को लेकर पीएम मोदी की दो टूक, कहा- नक्सलवाद की तरह करना होगा सफाया



पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे उग्रवाद को लेकर पीएम मोदी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों की तर्ज पर पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी समूहों के खिलाफ एक संयुक्त रूप से अभियान चलाने की जरूरत है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पीएम मोदी ने यह सुझाव राज्यस्थान के जयपुर में हाल ही में संपन्न हुए तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में दिया था। अधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें नए अपराधिक कानून, आतंकवाद विरोध रणनीतियां, वामपंथी उग्रवाद, उभरते साइबर खतरे और दुनियाभर में कट्टरवादी विरोधी मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने नागरिक पहले, गरिमा पहले, न्याय पहले की भावना पर जोर दिया है। साथ ही कहा कि नए अपराधिक कानून इन्हीं भावना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी ने पुलिस के मौजूद कर्मियों से कहा कि अब डंडा के बजाए डेटा पर अधिक जोर देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि नए कानून भारत की अपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव थे। साथ ही कहा कि महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों और नए कानूनों के तहत उन्हें सुरक्षा के बारे में जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश के कई शीर्ष पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पिछले वर्षों की तरह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था, जिसमें देशभर के कई स्थानों से विभिन्न रैंकों के 500 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था।

'कोयले पर रोक लाने का भारत ने किया था विरोध', कॉप-28 की बैठक का जिक्र करते हुए बोले भूपेंद्र यादव



पिछले वर्ष दिसंबर माह में दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के दौरान विकसित देशों ने कोयले पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो भारत ने ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करते हुए यह लड़ाई लड़ी। 'मोदी: एनर्जीइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर' पुस्तक का विमोचन के अवसर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार अमीर देशों को ग्लोबल साउथ के विकास में बाधा डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समारोह में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दुबई में हुई कॉप-28 की बैठक से जुड़ी बातों को साझा करते हुए कहा कि कोयले पर प्रतिबंध को लेकर विकसित राष्ट्र एक हो गए थे, लेकिन भारत ने ग्लोबल साउथ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि भारत ने उस वक्त तर्क दिया था कि अगर जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को छोटे देशों में गरीबी उन्मूलन से जोड़ा जाता है, तो उसे रोकना नहीं जा सकता है। दुबई में एक मसौदा समझौते के चैप्टर में कोयले को लेकर कठोर भाषा का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि यह वैकल्पिक था। जिसमें लिखा था कि कोयले से बिजली उत्पादन पर रोक लगाई जाए। मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी देश ऊर्जा पहुंच के बिना विकास नहीं कर सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हरित विकास हासिल करने पर जोर दे रहा है। बीते माह एक सम्मेलन में पत्रकारों के जवाब देते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा था कि भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गंगासागर मेले को लेकर ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा- केंद्र ने मदद की जरूरत तक नहीं समझी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि गंगासागर मेला को केंद्र ने मान्यता कभी नहीं दी है, जबकि गंगासागर मेला दुनिया के शानदार धार्मिक समागमों में से एक है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसके लिए मैंने केंद्र को कई पत्र लिखे, यहां तक यूनेस्को से भी इसको लेकर पत्राचार किया था। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के दौरान लाखों तीर्थयात्री गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर पवित्र स्थान के लिए इकट्ठा होते हैं। गंगासागर मेले के लिए केंद्र से नहीं मिला कोई सहयोग- ममता दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में एक आधिकारिक कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार केंद्र से कोई सहायता नहीं मिलने के बावजूद वार्षिक



आयोजन के लिए काम करती रहती है। इस दौरान केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा ममता बनर्जी ने कहा कि कुंभ मेला एक बड़ा मेला है, जिसे केंद्र से पूरी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि गंगासागर मेला, जो एक द्वीप पर आयोजित होता है। यह दुनिया के सबसे अच्छे मेलों में से एक है, पता नहीं केंद्र सरकार इसे

मान्यता क्यों नहीं दे रही है। अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार गंगा सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण कर रही है। ममता बनर्जी ने और 61 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कई बार केंद्र को सहयोग के लिए

लिखा पत्र- ममता बनर्जी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इसको लेकर कई बार केंद्र को पत्र लिखा है। लेकिन कभी भी कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया और न ही गंगासागर मेले के आयोजन के लिए पैसा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार अपने तरफ से गंगासागर मेला आयोजित कर रही है, लेकिन इसमें कोई सहयोग नहीं करता है। उन्होंने कहा कि मैंने यूनेस्को को भी पत्र लिखा था, जिसमें मैंने गंगासागर मेला को विरासत दर्जा देने का आग्रह किया था। हर साल लगभग एक करोड़ तीर्थयात्री यहां गंगा सागर मेले में पहुंचते हैं। यूनेस्को ने 2022 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) टैग प्रदान किया।

बांग्लादेश के चुनाव में जीत पर PM मोदी ने किया शेख हसीना को फोन, दोनों देशों के रिश्तों पर कही यह बात



विपक्षी दलों के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश में सात जनवरी को आम चुनाव हुए थे। इस दौरान बांग्लादेश के कई इलाकों में छुटपुट घटनाएं हुई थी। बांग्लादेश के आम चुनाव के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने प्रचंड जीत हासिल की है। 1300 में से 299 सीटों पर मतदान हुए, वहीं एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव टाल दिया गया था। 299 सीटों में से 223 सीटों पर आवामी लीग ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद पीएम मोदी ने शेख हसीना को फोन कर बधाई दी।

शेख हसीना को फोन कर दी बधाई- पीएम मोदी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री शेख हसीना से फोन पर बात हुई। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूँ। हम बांग्लादेश के साथ स्थायी और जन केंद्रित साझेदारी को अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत ही हमारा सच्चा दोस्त- शेख हसीना गौरतलब है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश ने जीत दर्ज करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया। उन्होंने कहा हमारा पड़ोसी देश भारत बांग्लादेश का सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है। 1971 और 1975 में भारत ने हमारा समर्थन किया था। मैं वास्तव में इस बात की सराहना करती हूँ कि भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध हैं। विपक्ष दलों के बहिष्कार के बीच बांग्लादेश में हुए थे चुनाव प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इससे पहले समय-समय पर विपक्षी दलों द्वारा लगातार बांग्लादेश में परिवहन नाकेबंदी की गई थी। गौरतलब है कि बीएनपी द्वारा कई बार हिंसक प्रदर्शन किए गए, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया था। विपक्ष का आरोप था कि मौजूदा पीएम शेख हसीना के रहते देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए।

डीओई ने नोटिस जारी कर महआ से पूछा- 'क्यों नहीं खाली किया बंगला?' तीन दिन में मांगा जवाब



तृणमूल कांग्रेस की पूर्व लोकसभा सांसद महआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर संपदा निदेशालय (डीओई) ने सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता को इससे पहले सात जनवरी तक आवास खाली करने को कहा गया था। डीओई ने अब उनसे तीन दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। सूत्र ने बताया, रमहुआ मोइत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार जनवरी को तृणमूल कांग्रेस नेता से कहा था कि वह डीओई से संपर्क कर अनुरोध करें कि उन्हें आर्बिट्रल सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने तृणमूल कांग्रेस नेता की उस आधिकारिक सूचना पर सुनवाई की थी जिसमें कहा गया था कि उन्हें निष्कासन के बाद आवंटन रद्द होने के कारण सात जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है।

50 साल पीछे जा चुके मणिपुर की ओर कब देखेगी सरकार? वरिष्ठ अफसर का छलका दर्द



आदमी को जन्मभूमि, अपनी मिट्टी से लगाव होता है। यह लगाव भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी को खाए जा रहा है। विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी का मूल राज्य मणिपुर है। कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। मणिपुर में ही उनका बचपन बीता, खेले और कहते हैं कि आज जो भी हूँ, मणिपुर ने बनाया है। हमारा राज्य रो रहा है। वहां की जनता घुट-घुट कर जी रही है। हमारे रिश्तेदार और करीबी वहां हैं और दिल्ली में रहकर हमारा भी दिल बैठा जा रहा है। विदेश सेवा के अधिकारी कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। कहते हैं विदेश सेवा का अधिकारी होने के कारण हमारे पास मणिपुर के लिए आवाज नहीं है, लेकिन वहां का दर्द है। विदेश मंत्रालय के एक कार्यक्रम में मिले सूत्र का कहना है कि केंद्र सरकार हमारे राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राज्य

सरकार के बस का कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कठपुतली की भूमिका में हैं। वह बताते हैं कि हमारा राज्य काफी फल-फूल रहा था। विकास की रफ्तार में था, लेकिन अब वहां के हालात हर दिन बद से बदतर हो रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वह वहां के समुदाय और लोगों के संपर्क में हैं। उन्हें जमीनी स्थिति काफी दर्द दे रही है। बताते हैं तमाम युवा दिल्ली में थे। रोजगार करते थे। हालात बिगड़े तो वह किसी तरह परिजनों का हाल जानने मणिपुर पहुंच गए। अब वहां उनकी जिंदगी फंसी हुई है। उनके पास दिल्ली या मणिपुर से बाहर निकलने के अब न तो संसाधन (पैसा) है और न रूट। जिसके पास जो रुपया पैसा, साधन था, वह खत्म हो गया है। इसी तरह से तमाम वहां युवा हैं, जो रोजगार और अपनी जिंदगी को राह देने के लिए छटपटा

रहे हैं। उनके सामने परिवार पालने और परिवार बसाने की चुनौती है। तमाम ऐसे भी प्रतिभाशाली हैं जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली समेत अन्य स्थानों पर भी आना चाहते हैं। भविष्य का सपना देख रहे हैं और उनके सपनों पर पानी फिर रहा है। सूत्र का कहना है कि मणिपुर 50 साल पीछे चला गया है। वहां मंहगाई चरम पर है। पाबंदियां भी हैं। खतरा भी और डर भी। यह वरिष्ठ अधिकारी अपना दर्द कुछ इस तरह बयान करते हैं 'आप पत्रकार हैं। बिना नाम छापे मेरा दर्द छाप दीजिए।' मणिपुर के बारे में पूछने पर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सरकार जो कदम उठा रही है, वह काफी है। सकारात्मक दृष्टिकोण का कोई संकेत नहीं दिखता। मेरे विचार में केन्द्र सरकार ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। राज्य सरकार के बारे में पूछने पर कहते हैं कि एन बीरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते। पावर विहीन मुख्यमंत्री हैं। सूत्र का कहना है कि सरकार को मणिपुर और भारत के हित में फैसला लेना चाहिए। वहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। मणिपुर के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में जाने के लिए सहायता देनी चाहिए। देश के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए

विशेष सहायता और सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। हजारों युवाओं को आज इसकी जरूरत है। सूत्र का कहना है कि प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे और वहां के लोगों का दर्द सुनकर आगे बढ़ने का मंत्र देंगे तो राज्य को बड़ी संजीवनी मिलने की संभावना है। सूत्र का कहना है कि मणिपुर के लोग बड़े मेहनती हैं। उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता पता है, लेकिन यहां तो रास्ते में ही खाई खोदी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल का दौरा वह कहते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 6700 किमी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर जाएंगे। वह अरुणाचल भी जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा? मणिपुर फिर कुछ दिन चर्चा में आ जाएगा। इससे तो कोई बदलाव होगा नहीं। हमारे राज्य में लोकसभा की बहुत सीटें भी नहीं हैं कि राजनीतिक पार्टियां बहुत चिंतित होंगी? लेकिन कहना चाहता हूँ कि मणिपुर देश का प्रमुख राज्य है। आज वहां हिंसा और तनाव का वातावरण पिछले छह महीने से अधिक समय से है। हमें केवल राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। सरकार की तो जिम्मेदारी बड़ी है। उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

ईडी अधिकारियों पर हमले को लेकर बोले डीजीपी- 'कानून तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना पर राज्य पुलिस ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने सोमवार को कहा, ईडी पर हमले के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुमार ने

स्पष्ट किया कि आरोपियों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राशन घोटाले की जांच के दौरान पिछले शनिवार को ईडी के के तीन अधिकारियों पर हमला किया गया था। साथ ही उनके

साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना वाले दिन जांच अधिकारियों की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना में स्थानीय तृणमूल नेता शेख शाहजहां के समर्थकों पर आरोप

लगा है। राज्य के डीजीपी सोमवार को सुरक्षा मामलों का जायजा लेने के लिए गंगासागर मेले में पहुंचे थे। ईडी अधिकारियों के सवाल पर उन्होंने कहा, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



सम्पादकीय

लोकतंत्र का सवाल

बांग्लादेश में रविवार को आम चुनावों के लिए मतदान हुआ। इस दौरान हिंसा और बहिष्कार की घटनाएं भी सामने आईं। इस चुनाव में वोट प्रतिशत काफी। ये इस बात को जाहिर करता है कि लोकतंत्र के कमजोर होने पर कैसे लोगों का चुनाव से भरोसा खत्म होने लगता है। पड़ोसी बांग्लादेश में रविवार को 12वें आम चुनाव हिंसा की घटनाओं और बहिष्कार की अपीलों के साये में संपन्न हुए। ये चुनाव इस बात का भी संकेत हैं कि किसी देश में लोकतंत्र के टांचे के बने रहते हुए भी अगर लोकतांत्रिक चेतना कमजोर पड़ने लगे तो वहां चुनाव लोगों की नजर में सार्थकता खोने लगते हैं। इसका सबूत यह है कि इन चुनावों में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। पहले चार घंटों में मात्र 18.5 फीसदी वोट दर्ज किए गए थे।

अंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकों की मौजूदगी : हालांकि जहां तक इन चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का सवाल है तो उस पर नजर रखने के लिए 100 से ज्यादा विदेशी प्रेक्षक बांग्लादेश में मौजूद हैं, जिनमें 3 भारतीय भी हैं। इन प्रेक्षकों की रिपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इंतजार करेगी, लेकिन देश के अंदर के माहौल की बात करें तो चुनावों के विरोध का भाव भले हो, इसके नतीजों को लेकर किसी तरह का सस्पेंस नहीं है।

विपक्ष नदारद : मतों की गिनती का काम सोमवार सुबह से शुरू होगा, लेकिन यह बात तय मानी जा रही है कि मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना फिर से सत्तारूढ़ होंगी। यह उनका कुल मिलाकर पांचवां और लगातार चौथा कार्यकाल होगा। परिणामों को लेकर इस तरह की निश्चितता की वजह यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी BNP इन चुनावों में हिस्सा ही नहीं ले रही। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भ्रष्टाचार के आरोपों में घर में नजरबंद हैं और उनकी पार्टी BNP ने इन चुनावों के बहिष्कार की अपील कर रखी है। चुनावों से पहले ही हजारों की संख्या में विपक्ष के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

कठिन चुनौतियां : वैसे, बांग्लादेश में लंबे समय से राजनीतिक स्थिरता रही है। शेख हसीना 2008 से लगातार सत्ता में हैं। उन्हें बांग्लादेश को आर्थिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने का श्रेय भी दिया जाता है। कुछ साल पहले तक बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री की बढ़त को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था। हालांकि 2022 के बाद से इसकी ग्रोथ पहले जैसी नहीं रही। अब चुनावों के बाद विपक्ष के असहयोग की संभावना को देखते हुए माना जा रहा है कि नई सरकार के लिए आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ाकर इकॉनमी को फिर से पटरी पर लाना शायद आसान न हो।

आंतरिक मामला : भारत सरकार ने ठीक ही यह एकदम स्पष्ट कर रखा है कि चुनाव पूरी तरह से बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और हाल के वर्षों में उनमें और सुधार देखने में आया है। बांग्लादेश की जमीन से भारत में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देने वाले तत्वों पर भी काफी हद तक लगाम लगाई गई है। चुनावों के बाद जो भी सरकार आएगी उसके साथ भारत अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने का काम जारी रखेगा।

गगनयान से क्या इसरो छु पाएगा आसमान? सूर्य और चंद्र मिशन के बाद भारत की अगली उड़ान

इसरो के सामने अभी तक की चुनौतियां मुख्य रूप से मिसाइल टेक्नॉलजी और टेलिकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़ी थीं। किसी चीज को रॉकेट पर सवार कराकर बहुत दूर फेंकना, फिर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के जरिये उसे सटीक ढंग से नियंत्रित करके मनचाही जगह पर ले जाना या कोई और मनचाहा काम लेना। पिछले पचास वर्षों में उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने से लेकर चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारने और उसकी सतह पर गाड़ी चलाने तक सारे काम इन दोनों तकनीकी श्रेणियों में ही आते रहे हैं। लेकिन यहां से आगे का चैलेंज बिल्कुल अलग तरह का है।

मानव युक्त मिशन इसरो के इस मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को 'गगनयान' नाम दिया गया है। हमारे लिए यह अमेरिका-रूस से कम लेकिन चीन की तुलना में थोड़ा ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। अमेरिका और रूस, दोनों को अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में सफलता 1961 में मिली थी। रूस ने 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन को पृथ्वी की कक्षा में भेजा और 108 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा करने के बाद उन्हें सफुल अफानी जमीन पर वापस उतार लिया। इसके 23 दिन बाद अमेरिका को भी इस मिशन में आंशिक सफलता मिली, जब उसके अंतरिक्षयात्री एलन शेपर्ड 5 मई 1961 को 15 मिनट के लिए अंतरिक्ष में गए और जीवित लौट

आए। तजुबों का फायदा चीन को ऐसी कामयाबी 15 अक्टूबर 2003 को हासिल हुई, जब उसके अंतरिक्षयात्री यांग लीवेई शेनझोऊ-5 अंतरिक्षयान से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचे और 21 घंटे में धरती के 14 चक्कर लगाकर पैराशूट से इनर मंगोलिया के रेगिस्तान में उतर आए। इससे चीन की वैज्ञानिक क्षमता पर मोहर जरूर लगी, लेकिन उसे थोड़ा फायदा रूसी और अमेरिकी तजुबों का भी मिला, जो तब तक विज्ञान के दस्तावेजों की तरह सार्वजनिक हो चुके थे। ज्यादा बड़ी बात यह कि शेनझोऊ-5 का ह्यूमन कैप्सूल काफी कुछ रूस के अति सफल सोयुज यान के डिजाइन पर आधारित था।

मदद मिलना मुश्किल चीनी वैज्ञानिकों ने सोयुज के डिजाइन में निश्चित रूप से काफी विकास किया, लेकिन इसमें कुछ भूमिका ब्लूप्रिंट के रूप में प्रत्यक्ष रूसी सहयोग की भी हो सकती है। यह जितनी भी रही हो, गगनयान के निर्माण में भारत को शायद उतनी भी न मिले। रूस क्या करेगा अभी पिछले साल, भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद इसरो ने अमेरिकी नेतृत्व वाली आर्टेमिस परियोजना में शामिल होने का फैसला किया था। जैसे कड़वे रिश्ते अभी अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष संगठनों के बीच बने हुए हैं, उसे देखते हुए इसरो को रूस से ऐसी

कोई अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ आर्टेमिस में शामिल होने के जो भी मायने इसरो के लिए निकलेंगे, उनका संबंध चंद्रमा से ही होगा। तकनीकी के लेनदेन में अमेरिका की कृपणता इतनी मशहूर है कि गगनयान के लिए उससे कुछ कहना बेकार है।

इसी साल परीक्षण साल के शुरू में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इसरो ने बता दिया है कि यूं तो 2024 में रेकॉर्ड 12 स्पेस मिशन उसे संपन्न करने हैं, लेकिन यह साल उसकी तरफ से 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान को ही समर्पित रहेगा। इससे जुड़े विविध पहलुओं को लेकर गठित टीमों पहले से ही काम कर रही हैं और उनको अपनी परियोजनाओं का परीक्षण इसी साल कर लेना है।

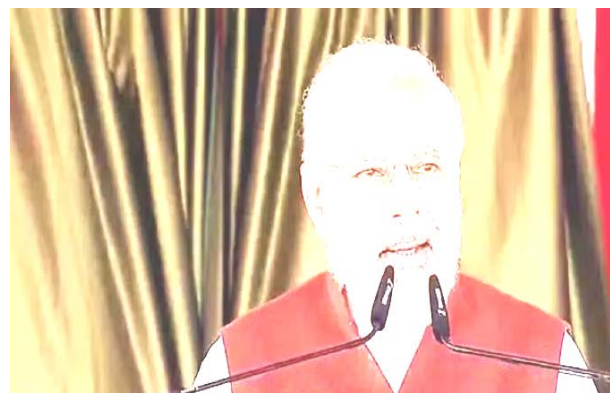
लड़का नहीं लौटी इस मिशन की कठिनाइयों पर गौर करें तो रूस ने मानवयुक्त अंतरिक्षयान की लॉन्चिंग से पहले जीवित शरीर पर इसके प्रभाव समझने के लिए 1957 में सड़क की एक कुतिया 'लड़का' को ह्यूमन कैप्सूल में बिठा दिया था। तमाम जीवों में उसी के चयन का आधार यह बनाया गया था कि विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रहने का तजुर्बा सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते में ही होता है। इसके अलावा उसके मादा होने और चमकीले बालों को उसकी जीवंतता का प्रमाण माना गया। अंतरिक्ष में जाने के बाद लड़का पर

बालकथाएं और गीत लिखे गए लेकिन उसका हुआ क्या, यह गोलमोल रह गया। यह जानकारी 2002 में सामने आई कि लॉन्चिंग का झटका तो लड़का झेल गई लेकिन पांच घंटे 104 डिग्री फॉरेनहाइट (40 डिग्री सेल्सियस) का तापमान नहीं झेल पाई। उसका मृत शरीर ही धरती पर लौटा था।

चिपेंजी झेल गया इस मामले में अमेरिकियों ने ज्यादा चतुराई दिखाई। उन्होंने इंसान का सबसे करीबी जीव समझा जाने वाला एक चिंपेंजी 1961 की जनवरी में स्पेस रवाना किया। अमेरिकियों के सारे हिसाब गलत निकले। यान को 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना था और 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बमशिकल पार करनी थी। लेकिन वह 150 किलोमीटर ऊंचा चला गया और उसकी रफ्तार भी 8000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो गई। यान की वापसी समुद्र में होनी थी, जहां वह अपनी तय जगह से 130 किलोमीटर दूर गिरा। जैसे-तैसे एक समुद्री जहाज ने उसे डूबने से बचाया, लेकिन चिंपेंजी न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि उड़ान में अपने टास्क भी पूरे किए। अजेंडे पर नहीं किसी मानवेंतर जीव की ऐसी कोई लॉन्चिंग न चीनी स्पेस एजेंसी (CNSA) के अजेंडे पर थी, न ही इसरो के अजेंडे पर है। मानव शरीर पर इसके प्रभावों का विस्तृत डेटा पहले से मौजूद है।

उत्कृष्ट लोक प्रशासन यानी लाभार्थी तक पहुंची सरकारी स्कीम; प्रधानमंत्री अवॉर्ड में बदलाव की तैयारी

पीएम मोदी आगामी 21 अप्रैल को देश के चुनिंदा सिविल सेवकों को सम्मानित करेंगे। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नागरिकों के जीवन में बड़े बदलाव लाने वाले इन पदाधिकारियों को सरकार हर साल सम्मानित करती है। हालांकि, इस साल अवॉर्ड से जुड़े पैमानों और नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने बताया कि, अब लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार (P M Awards) का पैमाना वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी स्कीम का लाभ पहुंचाना होगा। आधिकारिक बयान में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को कहा, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पुरस्कार की पूरी अवधारणा और प्रारूप में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन और योजनाओं को 'लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों तक पहुंचाने' (targeted individual beneficiaries) में उल्लेखनीय काम करने वाले लोक सेवकों को



केंद्र सरकार सम्मानित करेगी। सिविल सेवकों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए अवॉर्ड के नियमों को पुनर्गठित करने के बारे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने कहा, इस योजना का मकसद रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और संस्थागत तरीके से काम करने को प्रोत्साहित करना है। बयान के अनुसार, 'इस दृष्टिकोण के तहत, केवल मात्रात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों पर नहीं, अब सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम मील कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा।' इस साल पुरस्कार लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों के पैमाने पर दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए सोमवार को एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया।

सरकार के मुताबिक पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। आठ से 31 जनवरी, 2024 तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। वर्ष 2023 के पुरस्कार दो श्रेणियों- '12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत जिलों का समग्र विकास' और 'नवाचार यानी इनोवेशन' के तहत दिए जाएंगे। नवाचार श्रेणी के तहत छह पुरस्कार होंगे। लोक सेवकों को 20 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलता है पुरस्कारों के लिए अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जाएगी। पीएम अवॉर्ड 2023 के तहत लोक सेवकों को एक ट्रॉफी, एक स्क्रॉल और सम्मानित जिले या संगठन को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

फितना लाभप्रद होगा रोहित व कोहली का चयन

● टी20 टीम : क्या विश्व कप में भारत को भारी पड़ेगा ?

रोहित शर्मा और विराट कोहली को 14 महीने में पहली बार टी20 टीम में जगह देकर चयनकर्ताओं ने सुरक्षित रवैया अपनाया है लेकिन क्या उनका यह फैसला टी20 विश्व कप में भारत को भारी पड़ेगा? इसका पता समय आने पर ही चलेगा। पिछले दो टी20 विश्व कप में खिताब जीतने में नाकाम रहने के बाद रोहित और कोहली ने अगर एक और मौका देने की इच्छा जताई तो इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन चयनकर्ताओं के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता जिन्होंने नवंबर 2022 में सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली हार के बाद कई नए खिलाड़ियों को टीम में चुना था। रोहित और कोहली को अब



अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन टी20 मैच की श्रृंखला के लिए टीम में चुना गया है जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह दोनों दिग्गज अमेरिका और वेस्टइंडीज में जून में होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे। इन दोनों दिग्गज

खिलाड़ियों ने भारत को वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी लेकिन क्या वे खेल के सबसे छोटे प्रारूप की जरूरत से सामंजस्य बिठा पाएंगे। रोहित ने वनडे विश्व कप में शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया था और अफगानिस्तान के खिलाफ मोहाली

में शुरू होने वाली श्रृंखला में भी वह इसी अंदाज में खेल सकते हैं। दूसरी तरफ कोहली का खेल 50 ओवर के प्रारूप के अधिक अनुकूल है लेकिन उन्होंने जो 148 टी20 मैच खेले हैं उनमें 137.96 की अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसके विपरीत उनके साथी और विश्व के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट 170 से अधिक है। यशस्वी जायसवाल और रतुराज गायकवाड़ को जो भी मौके मिले हैं उनमें उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है लेकिन आईसीसी की प्रतियोगिता में अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। सुनील गावस्कर और सौरव गांगुली ने भी इसको महत्व देते हुए रोहित और कोहली को टी20 विश्व कप की टीम में शामिल करने की वकालत की थी। भारत के पूर्व चयनकर्ता शरणदीप सिंह ने भी रोहित और कोहली को टीम में शामिल करने का फैसला सही करार दिया। उन्होंने पीटीआई से कहा, यह सही फैसला है। आईसीसी की प्रतियोगिताओं में आपको ऐसे खिलाड़ी की जरूरत

पड़ती है जो अच्छी तरह से दबाव झेल सके। उन दोनों ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया और वे अच्छी फॉर्म में हैं। लेकिन इसके कारण जायसवाल और गायकवाड़ के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। रोहित और कोहली का चयन करके चयनकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा को लगता है कि चयनकर्ताओं को दोनों खिलाड़ियों का चयन करना था और वह इनमें से किसी एक को बाहर नहीं रख सकते थे। चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ऐसा लग रहा था कि वह अगले टी20 विश्व कप में नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्होंने पिछले विश्व कप के बाद इस प्रारूप में कोई मैच नहीं खेला था। उन दोनों की स्थिति अभी एक जैसी है। अगर चयनकर्ता किसी एक को बाहर भी रखने के बारे में सोचते, तो तब भी वह ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें इन दोनों का ही चयन करना था।

तोमर और ईशा को ओलंपिक कोटा

● एशियाई निशानेबाजी क्वालीफायर के 10 मीटर स्पर्धा में मिला स्वर्ण

भारत के युवा निशानेबाजों वरुण तोमर और ईशा सिंह ने सोमवार को यहां एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर की क्रमशः पुरुष और महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए दो ओलंपिक कोटा हासिल किए। इन दोनों के ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के साथ भारत के निशानेबाजों ने पेरिस खेलों के 15 कोटा हासिल कर लिए हैं और इसके साथ ही तोक्यो खेलों में सबसे अधिक निशानेबाज उतारने के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी कर ली। भारतीय



निशानेबाजों के पास बाकी क्वालीफायर स्पर्धाओं के जरिए भी इस साल जुलाई-अगस्त में होने वाले खेलों में जगह बनाने का मौका होगा। भारत ने इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के पहले दिन दो टीम स्वर्ण सहित कुल छह पदक के साथ अपने अभियान का आगाज किया। बीस साल के तोमर ने फाइनल में 239.6 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि उनके हमवतन अर्जुन चीमा ने 237.3 अंक के साथ रजत पदक जीता। मंगोलिया

के देवाखु एंखताइवान (217.2) ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले तोमर (586), अर्जुन (579) और उज्ज्वल मलिक (575) की भारतीय टीम कुल 1740 अंक के साथ टीम स्पर्धा में शीर्ष पर रही थी। ईरान और कोरिया ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। महिला वर्ग में 18 साल की ईशा ने फाइनल में 243.1 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान की किशमाला तलत (236.3) ने रजत जबकि ईशा की हमवतन रिदम सांगवान (214.5) ने कांस्य पदक जीता। ईशा, रिदम और सुरभि राव की भारतीय तिकड़ी ने कुल 1736 अंक के साथ टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। ईशा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम और 25 मीटर पिस्टल टीम के साथ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी है।

अनाहत 2024 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्ववाश में उप विजेता रही

बर्मिंघम (इंग्लैंड)। भारत की उभरती हुई स्टार खिलाड़ी अनाहत सिंह यहां ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के लड़कियों के अंडर-17 वर्ग में उप विजेता रही। अनाहत को रविवार को बर्मिंघम विश्वविद्यालय में 68 मिनट चले कड़े फाइनल में मिश्र की दूसरी वरीय नादीन अलहमामी के खिलाफ 2-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की 15 साल की अनाहत ने पहला गेम 11-7 से जीत लिया था लेकिन इसके बाद नादीन ने जोरदार वापसी करते हुए अगले दो गेम टाईब्रेक में 13-11 और 12-10 से जीतकर 2-1 की बढ़त बना ली। अनाहत ने चौथा गेम 11-5 से जीतकर स्कोर 2-2 किया लेकिन मिश्र की खिलाड़ी ने पांचवां और निर्णायक गेम 11-9 से जीतकर खिताब अपने नाम किया। पिछले महीने अनाहत ने स्कॉटिश जूनियर ओपन के अंडर-19 वर्ग का खिताब जीता था। इस बीच अमेरिकी जूनियर ओपन के लड़कों के अंडर-15 वर्ग के गत चैंपियन आर्यवीर दीवान लड़कों के अंडर-15 वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे। सेमीफाइनल में मिश्र के शीर्ष वरीय फिलोपेटर सालेह के खिलाफ 1-3 की शिकस्त के बाद आर्यवीर ने तीसरे स्थान के प्ले ऑफ में जीत दर्ज की। प्रतिभावान आदया बुधिया को लड़कियों के अंडर-13 क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की शीर्ष वरीय विविएन एसजे के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा।



यूबैक्स और मोनफिक्स ऑक्लैंड क्लासिक के पहले दौर में हारे

ऑक्लैंड (न्यूजीलैंड)। अमेरिका के क्रिस यूबैक्स और फ्रंस के दिग्गज गेल मोनफिक्स को एटीपी ऑक्लैंड क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में सोमवार को यहां हार का सामना करना पड़ा। पांचवी वरीयता प्राप्त यूबैक्स मासपेशियों के चोट के बाद बोर्डिकचैन डेर जैडस्युपुप की चुनौती से पार नहीं पा सका। उन्होंने मैच के बीच में इलाज के बाद अपना खेल जारी रखा लेकिन 6-7, 2-6 से हार गए। फ्रंस के 37 साल के मोनफिक्स के खेल पर भी उख हावी दिखी। हंगरी के पैक्सियन मरोज्जिन के खिलाफ वह तीन सेट के संघर्षपूर्ण मुकामले को 2-6, 7-6, 6-7 से गंवा बैठे।

क्रेसिकोवा और हदाद एडीलेड इंटरनेशनल के पहले दौर में हारे

एडीलेड (ऑस्ट्रेलिया)। फ्रेंच ओपन की पूर्व चैंपियन बारबरा क्रेसिकोवा और बौद्धि हदाद माइया को सोमवार को यहां एडीलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। छलीफायर अन्ना केलेन्सक्या ने 2021 की फ्रेंच ओपन विजेता और चौथी वरीय क्रेसिकोवा को 7-5, 3-6, 7-5 से शिकस्त दी। केलेन्सक्या तीसरे और निर्णायक सेट में जब 6-5 से आगे थी तो उन्हें क्रेसिकोवा की सर्विस पर तीन मैच ब्रेक मिले जिससे वे तीसरे पर अंक जुटाकर उन्होंने मैच अपने नाम किया।

आर्सेनल की मुश्किलें बरकरार, लीवरपूल से 0-2 से हारा

लंदन। आर्सेनल को एफए कप फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे दौर में लीवरपूल के खिलाफ रविवार को यहां 0-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी। आर्सेनल की टीम खराब फॉर्म से जूझ रही है और सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले सात मैच में से पांच गंवा चुकी है। टीम ने लगातार तीन मैच गंवाए हैं। रविवार को लीवरपूल के खिलाफ आर्सेनल के डिफेंडर याकूब किचियोर ने 80वें मिनट में आत्मघाती गोल किया जबकि लुई डियान ने इंग्रैडी टाइम के चौथे मिनट में गोल दागकर टीम को 2-0 से जीत सुनिश्चित की।

मंजीत ने जीता रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब

लखनऊ। राष्ट्रीय स्तर के शतरंज खिलाड़ी लखीमपुर के मंजीत सिंह ने द्वितीय सुनीता वर्मा मेमोरियल ऑल इंडिया रैपिड शतरंज चैंपियनशिप-2024 में सर्वाधिक 6.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। चेंस क्लब ब्लैक एंड व्हाइट लखनऊ द्वारा आयोजित 50 हजार की ईनामी राशि वाली इस चैंपियनशिप के सातवें व अंतिम राउंड में मंजीत को प्रयागराज के स्पर्श यादव ने ड्रा पर रोका। स्पर्श यादव को 6 अंक के साथ दूसरा स्थान मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रितिश जायसवाल व वर्तिका आर वर्मा रही जिन्होंने तीन-तीन अंक हासिल किए। दूसरी ओर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में लखनऊ के सईद अहमद व बहराईच के कमर नईम जिन्होंने अंतिम राउंड में समान 5.5 अंक हासिल किए। पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। इसी आयु वर्ग में महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी



की होड़ में इंद्राणी बसु 5 अंक के साथ पहले व महाना 3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। जूनियर वर्ग में लखनऊ के सुयश चंद्रा 6.5 अंक के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं लखनऊ के ही अभिनव वर्मा को 5.5 अंक के साथ दूसरा स्थान मिला। इस अवसर पर चेंस क्लब ब्लैक एंड व्हाइट ने पिछले 30 सालों में लखनऊ में शतरंज को बढ़ावा देने में अतुलनीय योगदान करने वाले निम्न दिग्गज खिलाड़ियों को

सम्मानित किया। वरिष्ठ खिलाड़ी और प्रशिक्षक देवेन्द्र बाजपेयी, आरिफ अली, सईद अहमद, पवन बाथम, जुनैद अहमद, शतरंज आयोजक देवेन्द्र नंदा और लखनऊ के फिडे इंटरनेशनल आर्बिटर हेमंत शर्मा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि अवध आईटीआई की प्रिंसिपल अग्नि शिखा वर्मा कर्ण एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

राष्ट्रीय टेनी क्वायट के लिए मुख्य दलनायक होंगे रफत

लखनऊ। श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश) में आयोजित आगामी 47वीं राष्ट्रीय सीनियर टेनी, क्वायट चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश की टीम सोमवार को रवाना हो गई। इस चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश टीम के मुख्य दलनायक (चीफ डि मिशन) डाइरेक्टर एम जुबैर रिजवी, सचिव उत्तर प्रदेश टेनी क्वायट एसोसिएशन होंगे। यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डाइरेक्टर किशोर पाण्डेय ने बताया कि 47वीं राष्ट्रीय सीनियर टेनी क्वायट चैंपियनशिप 9 से 13 जनवरी 2024 तक श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के गर्वनमेंट हाई स्कूल पलासा में होगी। चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाली 6 सदस्यीय टीम के कोच सिकंदर विलियम्स होंगे। टीम-पंकज कुमार, आदित्य यादव, पूरव नाहल, रोहित कुमार, कजल, सागर।



बीएआई 28 खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव का खर्च उठाएगा

नई दिल्ली। भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) इस साल सीनियर राष्ट्रीय पुरुष और महिला चैंपियन क्रमशः चिराग सेन और अनमोल खर्ब सहित 28 खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने का खर्च उठाएगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बोडब्ल्यूएफ) की रैंकिंग में 26वें से 75वें स्थान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ियों के अलावा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें इससे फायदा मिलेगा। इसके लिए पैसा बीएआई और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) की साझेदारी से आएगा। अबु धाबी मास्टर्स चैंपियनशिप में उन्नति हुई और 2023 बैडमिंटन एशिया अंडर-17 जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी शर्मा भी एकल और युगल वर्ग के उन 28 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें कई प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

बिलकिस मामले में 11 दोषी फिर जाएंगे जेल

सर्वोच्च अदालत ने कहा, गुजरात सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में अजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों की 2022 में समयपूर्व रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को अवैध करार देते हुए सोमवार को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने दोषियों को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में सजामाफी के मुद्दे पर फैसला लेना गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए सजामाफी का उसका फैसला रद्द किया जाता है। पीठ ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र की अदालत में हुई थी, इसलिए सजामाफी पर फैसला लेना वहां की सरकार के अधिकारक्षेत्र में आता है। पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार ने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग किया है। गुजरात सरकार की 1992 की माफी नीति के तहत बाकाभाई वोहानिया, जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशरभाई वोहानिया, प्रदीप मोढ़वाडिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को 15 अगस्त 2022 को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया



दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी

था। रिहा करने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। शीर्ष न्यायालय ने बिलकिस की याचिका और अन्य की याचिकाओं सुनवाई पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

नवम्बर 2022 में खटखटाया था अदालत का दरवाजा

बिलकिस ने नवंबर 2022 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका में उन्होंने दलील दी थी कि यह 'सबसे भयानक अपराधों में से एक था।' एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत से प्रेरित अत्यधिक अमानवीय हिंसा और क्रूरता थी। बिलकिस के अलावा सीपीआई (एम) नेता सुभाषिणी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती

लौल और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा और निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दोषियों को दी गई छूट के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अगस्त 2022 में दोषियों को रिहा करने का आदेश मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और पक्षपातपूर्ण था।

दंगों के दौरान 5 महीने की गर्भवती थीं बिलकिस बानों

गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिलकिस बानो के घर में घुस गई थी। दंगाइयों से बचने के लिए बिलकिस अपने परिवार के साथ एक

चुनावी फायदे के लिए 'न्याय की हत्या' की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि 'अपराधियों का संरक्षक' कौन है। बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है : **राहुल गांधी, कांग्रेस नेता**



बीजेपी सरकार ने बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में इन दोषियों को रिहा करने में मदद की है। मैं मांग करता हूँ कि गुजरात में बीजेपी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार को बिलकिस बानो से माफी मांगनी चाहिए: **असदुद्दीन ओवैसी, नेता एआईएमआईएम**



खेत में छिपी थीं। तब बिलकिस की उम्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती थीं। दंगाइयों ने बिलकिस का गैंगरेप किया। उनकी मां और तीन और महिलाओं का भी रेप किया गया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 6 लोग लापता पाए गए, जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिलकिस, एक शख्स और तीन साल का बच्चा ही बचे थे। गैंगरेप के आरोपियों को जनवरी 2008 में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी थी।

उपलब्धि

फोर्ब्स की सूची से मिली जानकारी

50 की उम्र के बाद भी महिलाएं दिखा रही अपनी ताकत

विश्व भर में ज्यादातर महिलाएं 50 की उम्र के बाद अपने करियर में आगे बढ़ती हैं और काश कि कंपनियां इस तथ्य को समझ पाती। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची की हालिया रैंकिंग महिलाओं को उनके जीवन और करियर के शीर्ष पर दर्शाती है। उनमें से 80 फीसदी 50 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और आधे 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं।

सभी रूढ़ियों और विरासत में मिली कहानियों, परियों की कहानियों और फिल्मों में वृद्ध महिलाओं को डरावनी व झुर्रीदार क्रोन के रूप में दिखाने के बावजूद उभरती हुई वास्तविकता यह है कि महिलाएं क्यू3 -उम्र की तीसरी तिमाही में हैं (50-75)। जो अपनी लंबी उम्र में कभी भी बेहतर नहीं दिखीं, फिट महसूस नहीं किया या अधिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। जीवन के सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में और यहां तक कि कुछ अप्रत्याशित देशों में भी महिलाएं



100 ताकतवर महिलाओं में से ज्यादातर 50 से अधिक उम्र की

पूरी तरह से आत्म-वास्तविक, मुखर और दृश्यमान हो रही हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को आगे बढ़ने में थोड़ा अधिक समय

उर्सुला वॉन एक आदर्श उदाहरण

वह महिला जो फोर्ब्स रैंकिंग में नंबर एक पर आई हैं एक आदर्श, उदाहरण है। उर्सुला वॉन डेर लेयेन 65 वर्षीय यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। वह 2005 में 46 साल की उम्र में एंजेला मर्केल की सरकार में परिवार और युवा मंत्री के रूप में शामिल हुईं और जल्द ही वहां से आगे बढ़ गईं।

लगता है। दरअसल, इसमें दशकों लग जाते हैं। अधिकांश पुरुष अपने 50 और 60 के दशक में बड़े समय की शक्ति और प्रभावशाली पदों पर पहुँचते हैं (तकनीकी क्षेत्र उल्लेखनीय

अपवाद है)। अधिकांश महिलाएं अभी भी क्यू-2 में पूंजीवाद, करियर और देखभाल के असंभव विरोधाभासों को पागलों की तरह सुलझाती हैं यानी वे औसतन थोड़ी देर से खिलती हैं।

अहमदाबाद में PM मोदी और UAE के राष्ट्रपति का रोड शो

9 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत होगी प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का रोड शो। पीएम मोदी खुद यूएई के प्रेसिडेंट को अहमदाबाद

एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और फिर दोनों नेताओं का रोड शो एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक होगा। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के आपसी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह समझिए कि UAE के प्रेसिडेंट पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और यह

उनकी चौथी भारत यात्रा होगी। दोनों नेताओं के शासनकाल में भारत और यूएई के रिश्ते एक अलग लेवल पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने नौ साल के शासनकाल में अब तक छह बार यूएई जा चुके हैं और अगले महीने फरवरी में एक बार फिर वो अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के बीच इस अंडरस्टैंडिंग का फायदा दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार पर पड़ा है। इस वक्त दोनों देशों के बीच लगभग 85 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है और संयुक्त अरब अमीरात, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

पृष्ठ 1/8 का शेष

मुख्यमंत्री के नाम दम भरने वाले

शिकायते प्राप्त हुई है लेकिन वह भी जीजाऊ कंट्रोलिंग कंपनी पर कार्यवाही करने से घबरा रहे हैं। शिकायतों का अम्बार लगा तो बालाजी होटल और मुंशी कम्पंड में दिखावे के लिए रोड थोड़ा बहुत कट कर के नया टुकड़ा डाला जा रहा है। आयुक्त के आदेश के बाद जबकि रोड बनते समय घटिया सामग्री जो डाली गयी निर्धारित खुदाई के अलावा जिस साइज के पत्थर दलाने थे वह सब नहीं डाला गया साथ ही आर एम सी जिस केटेगरी का चाहिए था वह भी नहीं डाला गया जिस के चलते पूरा सीमेंट का रास्ता खराब हो गया है लेकिन मनापा ने उन्हें अबतक सैकड़ों करोड़ रुपये बिल के रूप में अदा कर दिए हैं। मुख्यमंत्री का सब को दम भरने वाले जीजाऊ कंट्रोलिंग पर आय ए एस अधिकारी लगाम लगाएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही थी लेकिन वह भी नाकाम उम्मीद साबित हुई है। संजय काटकर भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। जीजाऊ कंपनी के घटिया निर्माण को देखते हुए और मनापा के अधिकारियों की नजर अंदाज किये जाने के चलते दूसर ठेकेदार भी अब घटिया निर्माण खुले आम कर रहे हैं। ऐसा ही एक अन्य ठेकेदार हबीब पटेल जोकि भोलानगर का सीसी रोड बना रहा है, विजय पटेल नामक ठेकेदार जो की उत्तन साइड में सीसी रोड बनाने का काम में जबरदस्त धांधली कर रहा है मन चाहा कार्य किया जा रहा है, रोड लेवल के लिए रेबीट, बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी साथ ही रोड का रेबीट भर कर सीसी रोड बनाया जा रहा है। अभियंता आँख बंद किये हुए हैं क्योंकि उक्त ठेकेदार विधायक प्रताप सरनाईक का करीबी माना जाता है। (क्रमशः)

भिवंडी में 2 दिन में 3 सड़क दुर्घटना की मौत 3 लोग घायल

डिवाइडर से जा टकराया इस दौरान बाइक चालक सूरज को गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। जबकि पीछे बैठा गुलाब घायल हो गया। इसी तरह ठाणे भिवंडी रोड पर स्थित काल्हेर में रहने वाले विनायक निकम अपनी पत्नी नंदा के साथ घरेलू सामान खरीदने के लिए 6 जनवरी को रात 8 बजे किराना दुकान पर जाने के लिए पैदल ही सड़क क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान एम एच 04 एल सी 4132 नंबर की तेजगति से आ रहे बाइक ने नियम को ताक पर रखकर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। इस दुर्घटना में सिर में जोरदार चोट लगने के कारण विनायक ने पत्नी के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नारपोली पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर फरार बाइक चालक पर दुर्घटना की जिम्मेदारी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह स्थानीय पूर्णा इलाके में 8 जनवरी की रात 12.15 बजे अशोक यादव व नीरज गुप्ता पैदल ही ठाणे रोड को क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान ठाणे की तरफ से आ रही कार ने दोनों को जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया। जिससे दोनों घायल हो गए हैं। नारपोली पुलिस फरार चालक पर दुर्घटना का केस दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। शहर व आस पास में बढ़ती दुर्घटना को लेकर राहगीरों में भय का माहौल व्याप्त है।

मीरा भायंदर मनापा को मिला वाटर प्लस रेटिंग

पहला क्रमांक और राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा क्रमांक हासिल किया था। स्वच्छता के प्रति समय समय पर मनापा द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों के कारण शहर के नागरिक भी अब स्वच्छता के प्रति जागरूक रहते हैं, गौरतलब है कि स्वच्छता के प्रमुख मापदंडों के आधार पर ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, सीवेज उपचार संयंत्र और उपचारित सीवेज का पुनर्चक्रण, सभी सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव व मरम्मत तथा शहर के सभी नालों की स्क्रिनिंग और सफाई, इन सभी का निरीक्षण करने के बाद ही मनापा को राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग से पुरस्कृत किया जाता है, और इस बार पुनः ओडीएफ, ओडीएफ + ओडीएफ ++ में मीरा भायंदर मनापा के उल्लेखनीय कार्य के लिए वाटर प्लस रेटिंग (plus rating) और प्रशस्ति पत्र (citation) देकर सम्मानित किया है। उपायुक्त रवि पवार ने बताया की पहली बार बार हमें यह वाटर प्लस पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह शहर के लिए गौरव की बात है।

लाख रुपया हफता नहीं दिया तो जेसीबी लगाकर कार्यालय तोड़ दिया

खोलने का विरोध करने लगे जिसके कुछ ही देर बाद वहां पर राकांपा के पूर्व नगरसेवक विकास पाटील अपने आदमियों के साथ जेसीबी लेकर आ गए और मामा भांजे के साथ गाली गलौच करते हुए उनके द्वारा रखे गए कंटेनर केबिन को जेसीबी से नेस्तनाबूत कर दिया जिसके बाद डरे सहमे उक्त लोगो नारपोली पुलिस स्टेशन में जाकर भिवंडी मनापा के पूर्व नगरसेवक विकास बालू पाटील, वीरेंद्र पाटील, निखिल विकास पाटील, रोहन कैलाश पाटील, जतीन विकास पाटील, वैभव वसंत पाटील, बंटी सालुंखे, दिनेश सुरेश भोईर व जेसीबी चालक सहित नौ लोगो पर सीआर नंबर 24/2024 में आईपीसी की धारा 384, 447, 427, 143, 147, 148, 149, 504 के तहत केस दर्ज कराया है। शिकायत का आरोप है कि पूर्व नगरसेवक के राजनैतिक रसूख के कारण व राजनीतिक दबाव में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि इस मामले में नारपोली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई भरत कामत से कॉल कर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनका मोबाइल नंबर कवरज क्षेत्र से बाहर होने के कारण बात नहीं हो सकी।

मुंबई पुलिस की मिसिंग स्कॉयड ने किया ऐसा काम, 2023 में लापता 98.7 प्रतिशत बच्चों को ढूंढ निकाला

में कामयाब रहे हैं। लड़कियों की गुमशुदगी को लेकर प्रशासन गंभीर पं त नगर पुलिस की तरह धारावी पुलिस ने भी 2023 में 35 लापता नाबालिग लड़कियों को बचाने का रेकॉर्ड कायम किया। इस थाने के तहत दर्ज मिसिंग केस को ट्रेस करने का रेकॉर्ड भी सौ प्रतिशत रहा है। धारावी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी राजू बिदकर बताते हैं कि उनकी मिसिंग स्कॉयड खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए समर्पित हैं। बिदकर का कहना है कि जब नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी की बात आती है तो हमें खास तौर सतर्क रहना होता है। कुशल नेतृत्व, मानवीय बुद्धिमत्ता और तकनीकी जांच की मदद से हमारी टीमों उन्हें ट्रेस कर उनके परिजन तक पहुंचाने का काम कर रही है। घर के बाहर रखे जूते से हुई बच्ची की पहचान मुंबई पुलिस के मुताबिक, पिछले दिनों घाटकोपर में एक आदमी ने एक नाबालिग का अपहरण कर लिया और उसको लेकर खोपोली के सूदूर गांव में जा छिपा। चूँकि, घने जंगलों के अंदर स्थित उस गांव में लड़की का पता मिलना चुनौती पूर्ण कार्य था। इसके बावजूद पुलिस ने गायब बच्ची के माता-पिता से उसका हुलिया, पहनावा और लापता होने के सम उसके जूते के रंग के बारे में पूछा था। आज भी छोटे घरों में रहने वाले लोग अपने जूते-चप्पल दरवाजे के बाहर रखते हैं। इसलिए मिसिंग स्कॉयड ने उक्त गांव के सभी घरों की जांच की। इस दौरान टीप को एक घर के बाहर बच्ची के माता-पिता द्वारा दिए गए विवरण वाला जूता मिल गया। वहां से ट्रैप लगाकर बच्ची को सकुशल रिहा किया गया। मानसिक रूप से बीमार बच्चा फुटपाथ पर सोता हुआ मिला मुंबई पुलिस के 'ऑपरेशन मुस्कान' अभियान के तहत मालाड के एक परिवार को नए साल पर अनोखा उपहार दिया। मानसिक रूप से बीमार 10 साल का बच्चा 1 जनवरी को लापता हो गया था, जिसे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने 36 घंटों के भीतर सकुशल ढूंढ निकाला। बच्चा मुंबई सेंटरल स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर सोता हुआ पुलिस को मिला। डीसीपी राज तिलक रौशन के नेतृत्व में दिंडोशी पुलिस ने बच्चों को उसके माता-पिता को सौंप दिया।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए मनापा भी तैयार

अधिकारियों की बैठक लेकर शहर की स्वच्छता और शहर को बदरूप करने वाली होर्डिंगों को हटाने का निर्देश दिया। बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को मुंबई आ रहे हैं। प्रधान मंत्री कोलाबा स्थित आई एन एस शिकरा के पास हेलीकाप्टर से आयेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद शिवडी स्थित एम टी एच एल (MTHL) पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्री वे से शिवडी तक जाएंगे। मनापा ने इस परिसर में आने वाले इलाको की साफ सफाई और परिसर में लगे बैनर पोस्टर को मुख्य रूप से हटाने का निर्देश मनापा उपायुक्त जोन 1 और जोन 2 को दिया। इस बैठक में मनापा के सहायक आयुक्त भी मौजूद थे। शिवडी नावा सेवा के बीच बने पुल जिसकी दूरी लगभग 21,8 किमी की है। इस पुल से मुंबई से नवी मुंबई की दूरी का अंतर कम किया गया है। मनापा आयुक्त चहल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है की सौदीयकरण के अंतर्गत लगाई गई एल ई डी लाइट जिस पर मोर बनाया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) का शहर को सुंदर बनाने की यह योजना है जिसमें किसी तरह की कोई कमी न दिखाई दे। एल ई डी लाइट को सभी सड़क के ट्रैफिक जंक्शन पर लगाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान शहर की सुंदरता में कोई कमी न रह जाए इसके लिए 1200 और मोर की दोहरी लाइटों को लगाने के लिए कहा गया है। सोमवार को मनापा आयुक्त की बैठक में साफ शब्दों में आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्ग पूरी तरह पानी से धोकर स्वच्छ करे और शहर mk सुंदर बनाने के लिए कदम उठाए। मार्ग पर विकसित भारत के संदेश के बोर्ड लगाए जाएं। संभावना है की मोदी वापस लौटते समय इसी मार्ग जा उपयोग करे इसके लिए सफाई और सुंदरता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। इस परिसर की दीवारों पर पेंटिंग कर दीवारों को सुंदर बनाया जाए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 6 और 7 जनवरी को इन्ही इलाको का दौरा कर साफ सफाई का जायजा लिया और शहर को सुंदर बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया।

बोरीवली से दहिसर तक के 35 ब्रिज होंगे चकाचक, बीएमसी कराएगी काम

लिया है। जिन ब्रिजों की मरम्मत होनी है, इनमें कुर्ला, साकोनाका में 6, गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजी नगर में 12 और चेंबूर में 8 ब्रिज शामिल हैं। इन ब्रिजों की मरम्मत पर बीएमसी 15.65 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसी तरह, घाटकोपर से लेकर मुलुंड तक छोटे-बड़े मिलाकर 42 ब्रिजों की मरम्मत का निर्णय लिया गया है। इस पर 27 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से लगभग सभी ब्रिजों, सबवे, नालों के ब्रिजों और स्काइवॉक की मरम्मत की जाएगी। बोरीवली में मरम्मत वाले ब्रिज बोरीवली (पश्चिम) स्काइवॉक, फैक्ट्री लेन ब्रिज, पावनधाम मंदिर ब्रिज, दौलतनगर सीमेंट्री, गोरई पंपिंग, इंद्रायणी नाला, शिवसृष्टि, एकसर नाला, एकसर नाला दरगाह के पास, साईबाबानगर, बोरीवली एसवी रोड, बोरभटपाडा, एकसर रोड कब्रिस्तान, गोरई नाला, मुलजी नगर, सावरकर गेट-3, कस्तूर पार्क, आनंदी बाई काले, म्हाडा कॉलोनी, सुयोग बिल्डिंग ब्रिज सहित 20 पुलों की मरम्मत की जाएगी। दहिसर में ब्रिजों की मरम्मत दहिसर न्यू ब्रिज, दहिसर ओल्ड ब्रिज, फिश मार्केट नाला, जयवंत सावंत, कोकणी पाडा, सेजय पार्क, पाटीलवाडी एफओबी, रतन नगर ब्रिज, रतन नगर एफओबी, रुस्तमजी ब्रिज, रुस्तमजी एफओबी, शांति नगर एफओबी, सेंट लुईस, वैशाली नगर और आईआर तावडे ब्रिज सहित 15 ब्रिजों की मरम्मत की जाएगी।

आखिरकार आ गई फैसले की घड़ी

पढ़ा जाएगा। फैसले की विस्तृत प्रति शिवसेना के दोनों गुटों को दी जाएगी। इस फैसले पर एकनाथ शिंदे सरकार का भविष्य टिका हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अयोग्यता मामले में फैसला तैयार है। नतीजों के मुद्दे पर दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से मजबूती से अपना पक्ष रखा गया। सुनवाई के दौरान हुई जिरह में दोनों गुटों ने यह साबित करने की कोशिश की कि उनका पक्ष कानून के अनुरूप है। 10 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे और उनके 16 विधायक अयोग्य घोषित होंगे या नहीं। यदि वे अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार गिर सकती है। अगर एकनाथ शिंदे पात्र घोषित किए जाते हैं और ठाकरे गुट के विधायक अयोग्य घोषित होंगे तो यह मामला सर्वोच्च अदालत की चौखट तक जा सकता है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर और मुख्यमंत्री के बीच रविवार 7 जनवरी को वर्षा बंगले पर चर्चा हुई थी। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा नहीं हो पाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय-सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय की। जून 2022 में, शिंदे और कई अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण शिवसेना में विभाजन हो गया और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस भी शामिल थी। शिंदे और ठाकरे गुटों (Shinde and Thackeray factions) द्वारा दलबदल रोधी कानूनों के तहत एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गईं। जून 2022 में विद्रोह के बाद शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल जुलाई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार गुट उनकी सरकार में शामिल हो गया था। निर्वाचन आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को 'शिवसेना' नाम और 'तीर धनुष' चुनाव चिह्न दिया, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना (यूबीटी) नाम और चुनाव चिह्न 'जलती हुई मशाल' दिया गया।

संभावित फैसले पर एक नजर

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नावेंकर क्या फैसला सुनाते हैं, इस पर सभी की निगाह लगी हुई हैं। वे चार में से कोई एक संभावित फैसला सुना सकते हैं। फैसला नंबर 1: यदि ठाकरे गुट के सचेतक सुनील प्रभु को व्हिप के अस्वीकार या उल्लंघन की बात सही पाई गई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। फैसला नंबर 2: केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे की पार्टी को शिवसेना नाम और धनुष बाण चुनाव चिह्न दिया है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष शिंदे गुट को मूल पार्टी मानकर ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहरा सकते हैं। फैसला नंबर 3: राहुल नावेंकर तटस्थ रहकर किसी भी गुट को अयोग्य नहीं ठहराते और यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल सकते हैं। फैसला नंबर 4: राहुल नावेंकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है।

लाख रुपया हफ्ता नही दिया तो जेसीबी लगाकर कार्यालय तोड़ दिया

पूर्व नगरसेवक सहित नौ लोगों पर हफ्ताखोरी, मारपीट का केस दर्ज दर्ज, कोई गिरफ्तार नहीं

सिटी न्यूज मुंबई/ भिवंडी में राकांपा के पूर्व नगरसेवक की दादागिरी का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। 15 लाख रुपया बतौर हफ्ता न देने से नाराज पूर्व नगरसेवक ने अपने आदमियों के साथ न सिर्फ जमीन मालिक के साथ गालीगलौच की बल्कि जेसीबी द्वारा उनके कंटेनर कार्यालय को नेस्तनाबूत कर दिया। इस मामले में जमीन मालिक ने पूर्व नगरसेवक सहित नौ लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार



नही किया है। उक्त घटना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने बताया कि भिवंडी के सोनीबाई कंपाउंड में रहने वाले शिवाकांत पांडे ने नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में बताया है

कि उनके मामा प्रविणचंद पांडे ने अपनी पत्नी प्रमिला पांडे व शीला त्रिपाठी ने नाम पर नारपोली इलाके में सर्वे नंबर 116/12 पर 11 गुंठा जमीन 25 अक्टूबर 2023 को खरीदा था जिस पर उक्त लोग ट्रांसपोर्ट की

गाड़ी पार्क करते थे। उन्होंने बताया कि इसी जमीन पर ट्रांसपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए 5 जनवरी 2024 को रात 8.30 बजे एक रेडीमेंट कंटेनर केबिन लाकर रखा था जिसके बाद पांच लोग उस जगह पर आए और धमकी देने लगे कि 5 लाख रुपया दो वर्ना कार्यालय नही खोलने देंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि 7 जनवरी को अपने मामा के साथ सुबह 10.30 बजे वे लोग कंटेनर केबिन को शुरू करने के लिए कलर कर रहे थे। इसी दरम्यान पुनः पांच लोग आए और पैसा न देने पर कार्यालय **शेष पृष्ठ 7 पर**

भिवंडी में 2 दिन में 3 सड़क दुर्घटना, 2 की मौत 3 लोग घायल



सिटी न्यूज मुंबई/गनी खानभिवंडी के अलग अलग क्षेत्रों में दो दिन में हुए 3 सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि 3 लोग घायल हो गए। जिसमें से दो दुर्घटनाएं सड़क क्रॉस करने के दौरान घटी। जबकि एक बाइक सवार डिवाइडर से टकराकर अपनी जान गवा बैठा। पुलिस के अनुसार कोनगांव के गिरिधर नगर में रहने वाला सूरज राजभर (24) अपने मित्र गुलाब मोरे के साथ शनिवार की रात एक बजे बाइक क्रमांक एम एच 04 एल जी 6080 द्वारा भिवंडी शहर की तरफ कल्याण रोड द्वारा जा रहा था। कुछ दूर पर जाने के बाद तेजगति की बाइक से उसका नियंत्रण छूट गया और बाइक **शेष पृष्ठ 7 पर**

मीरा भायंदर मनपा को मिला वाटर प्लस रेटिंग



भायंदर। केंद्र सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अभियान के तहत प्रतियोगिता का आयोजन किया था, और इस अभियान में कचरा मुक्त शहर, ओडीएफ प्लस में उल्लेखनीय कार्य के कारण मीरा भायंदर मनपा को वाटर प्लस रेटिंग (water plus rating) दी गई है। ज्ञात हो कि मीरा भायंदर मनपा ने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या समूह में राज्य में **शेष पृष्ठ 7 पर**

बोरीवली से दहिसर तक के 35 ब्रिज होंगे चकाचक, बीएमसी कराएगी काम

मुंबई: बीएमसी बोरीवली से दहिसर के बीच 35 ब्रिज की मरम्मत करेगी। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें ब्रिज, सबवे, नाले के पुल, स्काइवॉक की मरम्मत शामिल है। जिन ब्रिजों की मरम्मत होनी है, उनमें 15 दहिसर और 20 बोरीवली एरिया में हैं। बीएमसी 2018 में हुए अंधेरी के गोखले ब्रिज दुर्घटना से सबक लेते हुए लगातार ब्रिजों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर रही है। बीएमसी ब्रिज डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि वर्कऑर्डर जारी होने के 24 महीने के भीतर इन ब्रिजों की मरम्मत करना ठेकेदार के लिए अनिवार्य



होगा। अधिकारी ने बताया कि मुंबई में कई ऐसे ब्रिज हैं, जो 100 साल पुराने हैं और ज्यादातर को बने 30 से



50 साल हो गए हैं। 2018 में गोखले ब्रिज दुर्घटना के बाद करीब 300 ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट की किया

गया। स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट में कुछ ब्रिजों को तोड़ कर दोबारा बनाने, कुछ में मेजर मरम्मत और कुछ में मामूली मरम्मत और कुछ ब्रिजों को बाद में मरम्मत की जरूरत की सिफारिश की गई थी। अंधेरी दुर्घटना के बाद बीएमसी हर 6 महीने में सभी ब्रिजों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने लगी है। इसी जांच में इन ब्रिजों की मामूली मरम्मत की सिफारिश की गई थी। सभी ब्रिज हैं कतार में बीएमसी ने इससे पहले पहले उपनगर में कुर्ला, साकोनाका, गोवंडी, मानखुर्द और चेंबूर के 26 ब्रिज की मरम्मत करने का निर्णय **शेष पृष्ठ 7 पर**

मुंबई पुलिस की मिसिंग स्कॉयड ने किया ऐसा काम, 2023 में लापता 98.7 प्रतिशत बच्चों को ढूँढ निकाला

मुंबई: नए साल के उपलक्ष्य में मुंबई पुलिस उपहार स्वरूप करीब 90 परिवारों के मायूस चेहरों पर मुस्कान लौटाकर मानवता की मिसाल पेश की है। इसे मुंबई पुलिस की 'मिसिंग स्कॉयड' ने कामयाब किया है। इससे जाहिर होता है कि मुंबई पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए दौड़-भाग करती है, बल्कि पुलिस का दूसरा चेहरा मानवीय भी होता है। मालवणी, दिंडोशी, समता नगर, धारावी और पंत नगर समेत 93

पुलिस थानों द्वारा बीते साल उनके हद से गायब हुए 6649 बच्चों में से 6735 बच्चों की शत-प्रतिशत ट्रेसिंग के बाद से साफ हो गया है पुलिस खोए हुए चेहरे पर मुस्कान लाने में भी काबिल हैं। पीएसआई सुभाष हामरे और सिपाही सोनाली शिंदे, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों से करीब 24 लड़कियों और 6 लड़कों को सफलतापूर्वक रिहा करा पाए का कहना है कि घरेलू दुर्व्यवहार और



प्रेम संबंध के कारण अधिकतर बच्चे घरों से भागते हैं या गायब हो जाते हैं। बता दें कि खोए हुए बच्चों की तलाशी के लिए मुंबई पुलिस 'ऑपरेशन मुस्कान' नामक अभियान संचालित करती है। रूप बदलकर करते हैं खोए हुए बच्चों का रेस्क्यू पंत नगर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश केवले बताते हैं कि पुलिस की मिसिंग स्कॉयड बेहतरीन काम कर रही है, जो हर गुजरते साल के साथ बेहतर होते जा रहा है। पिछले वर्ष भी

हम अपने थाने में दर्ज मिसिंग के सभी केसों को हल कर गायब रहे नाबालिगों को बचाने में कामयाब हुए थे और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि, इन बच्चों को सकुशल रिहा करने के हमारे पुलिसकर्मियों को लोन एजेंट, डाकिया, ग्राहक, आरटीओ अधिकारी आदि बनने पड़े थे। बता दें कि पंत नगर पुलिस स्टेशन के मिसिंग स्कॉयड ने 30 नाबालिग बच्चों को 2023 में बचाने **शेष पृष्ठ 7 पर**